कानपुर, गुरुवार, 08 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 12, पृष्ठः 8+4
प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी
सच्चाई के दम पर जोश के साथ...
www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड भारत से डीज़ल खरीदेगा बांग्लादेश ! >Pg12
एसआईआइर से बदल गया यूपी का सियासी गणित!... > Pg07

मूल्यः 2 ₹

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इस महीने के अंत में उद्घाटन, तीन घंटे कम होगा सफर

हावड़ा-गुवाहाटी के बीच स्लीपर वंदे भारत अब आ रही ट्रैक पर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

गुवाहाटी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही अपनी पहली यात्रा पर रवाना होने जा रही है। यह अत्याधुनिक सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में इस बहुप्रतीक्षित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में करीब तीन घंटे की कमी आएगी। वर्तमान में इस रूट पर सरायघाट एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन है, जो लगभग 966 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे से अधिक समय लेती है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से यह सफर घटकर करीब 14 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है, जिससे रात भर की यात्रा अधिक आरामदायक और समय बचाने वाली होगी।

यह ट्रेन यात्रा का अनुभव बदल देगी

यह ट्रेन आईसीएफ तकनीक पर आधारित है और इसे बीईएमएल द्वारा विकसित किया गया है। इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। आधुनिक स्लीपर कोच, बेहतर सस्पेंशन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के साथ यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल देगी। हावड़ा-गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सप्ताह में छह दिन संचालित की जाएगी।

रात भर की यात्रा को ध्यान में रखकर

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का विस्तार सभी राज्यों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों को विशेष रूप से करीब 1,500 किलोमीटर तक की रात भर की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। रेलवे का मानना है कि इंटेलिजेंट डिजाइन और हाई-स्पीड क्षमताओं के जरिए यह ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा में समय, सुविधा और विश्वसनीयता-तीनों को नया स्तर देंगी।

180 किमी प्रतिघंटा डिजाइन स्पीड, सप्ताह में छह दिन चलेगी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन

जीएसटी में इंस्पेक्टर राज पर लगाम सचल दल किए जाएंगे खत्म

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- अब सड़क पर नहीं रुकेगी गाड़ी, इंटेलिजेंस इनपुट पर होगी कार्रवाई
- व्यापारियों के उत्पीड़न से राहत, आयकर विभाग जैसी होगी नई कार्यप्रणाली

लखनऊ। जीएसटी के तहत कारोबारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए राज्य कर विभाग ने एक बड़ी और अहम पहल की है। विभाग अब सचल दल इकाइयों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत सड़कों पर जगह-जगह वाहनों को रोककर कागजात जांचने की व्यवस्था खत्म की जाएगी और इंटेलिजेंस आधारित कार्यप्रणाली लागू की जाएगी।

राज्य कर विभाग ने ग्रेड-2 के सभी अपर आयुक्तों से सचल दल इकाइयों की उपयोगिता, गुणवत्ता और कार्यशैली का विश्लेषण करते हुए प्रस्ताव मांगा है। विभाग का स्पष्ट मानना है कि ऑन-स्पॉट चेकिंग से जहां व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ी हैं, वहीं इससे विभाग पर इंस्पेक्टर राज का आरोप भी लगता रहा है।

अब नई व्यवस्था में जीएसटी चोरी से जुड़े पुख्ता इनपुट और डेटा एनालिसिस के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। बिना ठोस जानकारी के किसी भी वाहन या कारोबारी को रोककर जांच नहीं होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, भविष्य में सचल दल की भूमिका आयकर विभाग की तर्ज पर होगी, जहां छापेमारी या जांच से पहले पूरी जानकारी जुटाई जाती है। सचल दल की बदली भूमिका के लिए एक विशेष इंटेलिजेंस टीम गठित करने की भी योजना है। यह टीम जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के कारोबार पर नजर रखेगी, गोपनीय जानकारियां जुटाएगी और डेटा एनालिसिस के जरिए टैक्स चोरी के मामलों की पहचान करेगी। आंकड़ों में असामान्यता पाए जाने पर ही कार्रवाई की जाएगी, जिससे बड़ी और संगठित टैक्स चोरी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। इस नई व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट मुरादाबाद में चल रहा है। यहां जुटाए गए डेटा के आधार पर लोहे, लकड़ी के कारोबारियों और ईंट-भट्ठा संचालकों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि, सभी पहलुओं का आकलन अभी किया जाना बाकी है। सभी अपर आयुक्तों से प्रस्ताव मिलने के बाद विभाग पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने पर अंतिम निर्णय लेगा।

लगभग 600 अधिकारी और कर्मचारी तैनात

वर्तमान में प्रदेश में जीएसटी की 140 सचल दल इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 600 अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। विभाग का मानना है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स चोरी के तरीके बदल चुके हैं और परंपरागत चेकिंग से बड़े मामलों पर रोक लगाना संभव नहीं है। ऐसे में इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम ही टैक्स चोरी पर प्रभावी अंकुश लगा सकता है।

जनता दरबार में सीएम योगी का फरमान अवैध कब्जा करने वालों को भेजे जेल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- बिना भेदभाव मिले न्याय, जरूरतमंदों को तुरंत मिले मदद

गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि हर पीड़ित को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिले। उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने और दबंगों पर सख्ती से कानून का शिकंजा कसने के निर्देश दिए।

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 150 फरियादियों की समस्याएं सुनीं। वे स्वयं कुर्सियों तक पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनते नजर आए। सभी प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर आए लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद मरीजों के उच्च स्तरीय उपचार का आकलन शीघ्र तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराया जाए, ताकि तुरंत धन जारी किया जा सके।

इससे पहले गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाया। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला में गोसेवा की और गोवंश को गुड़ खिलाया। इस दौरान उन्होंने परिजनों के साथ आए बच्चों से मुलाकात कर उन्हें स्नेह, आशीर्वाद और चॉकलेट भी दी।

आपदा में उजड़े परिवारों को सरकार का 'मरहम'

» आकाशीय बिजली से सर्पदंश तक, आपदा राहत से 48 घंटे में पहुंचा मुआवजा

107 मामलों में 4.28 करोड़ की सहायता

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । बिल्हौर तहसील के ग्राम पलिया बुजुर्ग में आकाशीय बिजली गिरने से 34 वर्षीय सरोज कुमार की मौत के बाद परिवार के सामने जीविका का गहरा संकट खड़ा हो गया था। घर का कमाने वाला सदस्य अचानक चला गया और पत्नी पूजा के सामने रोज़मर्रा की जरूरतों से लेकर भविष्य तक की चिंता एक साथ आ खड़ी हुई। ऐसे कठिन समय में प्रदेश सरकार की दैवीय आपदा राहत योजना पीड़ित परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। शासन की ओर से अनुमन्य चार लाख रुपये की सहायता राशि महज 48 घंटे के भीतर सीधे खाते में पहुंच गई, जिससे परिवार को तत्काल आर्थिक संबल मिल सका।

सरोज कुमार का मामला अकेला नहीं है। घाटमपुर क्षेत्र में तालाब में डूबकर हुई मृत्यु के बाद एक परिवार को राहत दी गई, वहीं थाना पनकी क्षेत्र में अग्निकांड में जान गंवाने वाले गृहस्थ के परिजनों को भी आपदा राहत राशि उपलब्ध कराई गई। इसी तरह सर्पदंश से हुई मृत्यु के एक मामले में भी शासन से अनुमन्य सहायता पीड़ित परिवार तक पहुंचाई गई। सभी मामलों में राहत राशि को समयबद्ध ढंग से सीधे खातों में हस्तांतरित की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जनपद में 107 दुर्भाग्यपूर्ण हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के खातों में कुल 4 करोड़ 28 लाख रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इनमें डूबने से हुई 63, आंधी-तूफान से 6, वनरोज के आघात से 1, आकाशीय बिजली से 6, सर्पदंश से 9, अतिवृष्टि से 8 तथा अग्निकांड से 14 मौतें शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में 71 जनहानि के मामलों में कुल 2 करोड़ 84 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। इनमें डूबने से हुई 45, वनरोज से 3, आकाशीय विद्युत से 7, अतिवृष्टि से 4 तथा अग्निकांड से 7 मौतें शामिल थीं।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41 जनहानि के सापेक्ष कुल 1 करोड़ 64 लाख रुपये की सहायता पीड़ित परिजनों को उपलब्ध कराई गई, जिनमें डूबने से हुई 28, आकाशीय विद्युत से 4, अतिवृष्टि से 4 तथा सर्पदंश से हुई 5 मौतें शामिल थीं।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट प्राथमिकता है कि आपदा की स्थिति में पीड़ित परिवारों को त्वरित, पारदर्शी और सम्मानजनक सहायता मिले। इसी निर्देश के तहत जनपद स्तर पर एक विशेष मैकेनिज्म विकसित किया गया है, जिससे सभी प्रकरणों की त्वरित जांच कर राहत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े।

क्या है दैवीय आपदा राहत योजना

प्रदेश सरकार की दैवीय आपदा राहत योजना के तहत प्राकृतिक या आकस्मिक आपदाओं में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रित को आर्थिक सहायता दी जाती है। डूबने, आकाशीय बिजली, सर्पदंश, अग्निकांड, आंधी-तूफान, अतिवृष्टि और वन्य जीव के आघात जैसी घटनाएं इस योजना में शामिल हैं। जनहानि की स्थिति में मृतक के आश्रित को सामान्यतः 4 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। घटना की सूचना के बाद राजस्व विभाग द्वारा जांच कर प्रकरण राहत पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और स्वीकृति के उपरांत राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है।

आपदा राहत: संक्षेप में

सहायता राशि (जनहानि)- 4 लाख
भुगतान समय- 48 से 72 घंटे के भीतर

वर्ष 2025-26 (अब तक)

107 जनहानि ₹ 4.28 करोड़
मृत्यु के कारण (2025-26)
डूबना 63 ₹ आंधी-तूफान 6 ₹ वनरोज आघात 1 ₹ आकाशीय बिजली 6 ₹ सर्पदंश 9 ₹ अतिवृष्टि 8 ₹ अग्निकांड 14

पिछले वर्ष-

2024-25- 71 जनहानि ₹ 2.84 करोड़
2023-24- 41 जनहानि ₹ 1.64 करोड़

अवैध कब्जों पर चला केडीए का बुलडोजर

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में जोन-04 क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण जयंती विस्तार पार्ट-3 में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण की भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए। 07 जनवरी 2026 को की गई इस कार्रवाई में प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान का नेतृत्व प्रभारी अधिशासी अभियंता सुधांशु श्रीवास्तव तथा प्रवर्तन प्रभारी द्वारा किया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अन्य अभियंता, प्रवर्तन कर्मी एवं पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।कार्रवाई के दौरान लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले चार अलग-अलग भूखंडों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। मौके पर बनी अस्थायी संरचनाओं को हटाकर भूमि को पुनः कानपुर विकास प्राधिकरण के अधीन कर लिया गया।प्रवर्तन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे।इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया, वहीं स्थानीय नागरिकों ने प्राधिकरण के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे शहर के नियोजित विकास की दिशा में जरूरी बताया।

नगर आयुक्त से मिले बसपा नेता

मायावती के जन्मदिन पर कानपुर में भव्य आयोजन की तैयारियां तेज

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन को लेकर कानपुर में जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में 15 जनवरी को पनकी स्थित रामलीला मैदान, रतनपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। कार्यक्रम को 'जन कल्याणकारी दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

आयोजन को लेकर बसपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर कार्यक्रम की अनुमति और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। युवा बसपा नेता रवि गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मायावती के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और जनकल्याण के संदेश को आगे बढ़ाया जाएगा।ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व आईएफएस और मुख्य मंडल प्रभारी बी आर अहिरवार, जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार अधिवक्ता, युवा बसपा नेता रवि गुप्ता, पूर्व मंडल प्रभारी राम नारायण निषाद, राम शंकर कुरील और प्रभारी धर्मेंद्र गौतम शामिल रहे।

बसपा नेताओं ने नगर प्रशासन से कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपेक्षा जताई है। वहीं कार्यकर्ताओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

प्रेमी ने महिला को मार डाला

खेत से 8 महीने बाद निकला कंकाल

प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

- बेटे की शिकायत पर खुला राज, सजेती में रातभर चली खुदाई
- हाईटेंशन पोल के नीचे दफनाया गया शव, डीएनए जांच की तैयारी

कानपुर। सजेती थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके प्रेमी ने शव को खेत में दफना दिया। करीब आठ महीने तक यह राज दफन रहा, लेकिन बेटे की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार रात खुदाई कराई, जहां से महिला का कंकाल बरामद हुआ। घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

मामला टिकवांपुर गांव का है। यहां रहने वाली 45 वर्षीय रेशमा अपने पति रामबाबू संखवार की पांच वर्ष पूर्व कैंसर से मौत के बाद पड़ोसी और पति के चचेरे भाई गोरेलाल संखवार के साथ रहने लगी थी। गोरेलाल अविवाहित था। रेशमा के चार बेटे और तीन बेटियां हैं। बेटे बबलू के मुताबिक, अप्रैल 2025 में गोरेलाल उनकी मां को साथ लेकर इटावा गेहूं कटाई के लिए गया था। इसके बाद से रेशमा का कोई सुराग नहीं मिला। पूछताछ पर गोरेलाल लगातार यही कहता रहा कि वह इटावा से कहीं और चली गई है।

शक तब गहराया जब 29 नवंबर को एक पारिवारिक शादी समारोह में गोरेलाल ने रेशमा के बारे में पूछने पर कह दिया कि अब वह इस दुनिया में लौटकर नहीं आएगी। इसके बाद बबलू ने मां की तलाश की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो 29 दिसंबर को सजेती पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने गोरेलाल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जहां वह टूट गया और हत्या कर शव खेत में दफनाने की बात कबूल कर ली।

पुलिस के अनुसार, इटावा से लौटने के बाद गोरेलाल ने रेशमा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गांव के बाहर धरमंगतपुर रोड स्थित एक ट्यूबवेल के पास खेत में गाड़ दिया।

शव को हाईटेंशन बिजली पोल के ठीक नीचे इस तरह दफनाया गया था कि वहां जुताई न हो सके। इसी वजह से लंबे समय तक किसी को हत्या की भनक नहीं लगी। वर्तमान में उसी खेत में गेहूं की फसल खड़ी है।

शव जिस तरह से गहराई में और सुनियोजित ढंग से दफनाया गया, उससे अन्य लोगों की संलिप्तता की आशंका भी जताई जा रही है। मृतका के बेटे बबलू ने गोरेलाल के साथ उसके भाइयों सुरेश और मुन्नू पर भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने गोरेलाल समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, हालांकि पूछताछ में गोरेलाल खुद को ही हत्या का जिम्मेदार बता रहा है। खुदाई के दौरान शव पूरी तरह गल चुका था और सिर्फ कंकाल बरामद हुआ। सजेती थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि कंकाल की डीएनए जांच कराई जाएगी ताकि पहचान की औपचारिक पुष्टि हो सके। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

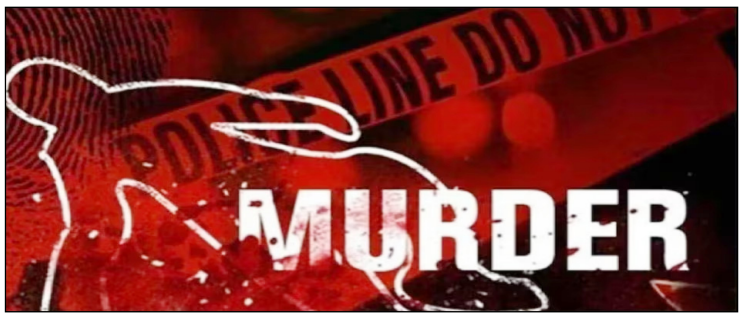

युवक की ईंट से कूंचकर हत्या

खाली प्लॉट में खून से लथपथ मिला शव

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

- घर से थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर निकला था युवक

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। हमलावरों ने युवक के सिर पर ईंट से वार कर उसे मरणासन्न हालत में छोड़ दिया। बुधवार सुबह युवक का खून से लथपथ शरीर घर से करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में मिला। घटनास्थल के पास खून से सनी ईंट भी बरामद हुई है।

नानकारी, प्रधान गेट निवासी रामवीर का 30 वर्षीय बेटा गांधी सोनू मंगलवार शाम करीब पांच बजे घर से यह कहकर निकला था कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला।

बुधवार सुबह मोहल्ले के बच्चे खाली प्लॉट के पास क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान गेंद प्लॉट के अंदर चली गई। बच्चे जब अंदर पहुंचे तो सोनू खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। उसके सिर और कान से खून बह रहा था। यह देखकर बच्चे घबरा गए और बाहर आकर परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सोनू को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई मोनू ने बताया कि सोनू विश्वविद्यालय परिसर स्थित एसीपी कल्याणपुर कार्यालय में सफाई कर्मचारी था, हालांकि पिछले छह महीनों से वह काम पर नहीं जा रहा था। कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्र कांत शुक्ला ने बताया कि परिजनों ने किसी भी तरह की पुरानी रंजिश से इनकार किया है। युवक शराब का आदी था, ऐसे में आशंका है कि नशे की हालत में किसी विवाद के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया हो। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

जाजमऊ चमड़ा टेनरी में जहरीली गैस से मजदूर की मौत

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

- एक हफ्ते तक मामला छिपाए रखा, इलाज के दौरान तोड़ा दम
- मुआवजे को लेकर परिजनों का हंगामा, पुलिस जांच में जुटी

कानपुर। जाजमऊ इलाके में टेनरी उद्योग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर सामने आई है। संजय नगर स्थित हुमेरा टेनरी में काम के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 37 वर्षीय मजदूर शिव कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते बुधवार को चमड़े के ढोल में काम करते समय गैस का रिसाव हुआ, जिससे शिव कुमार मौके पर ही बेहोश हो गए।

आनन-फानन में टेनरी प्रबंधन ने उन्हें रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन घटना को दबाए रखा गया। गुरुवार को इलाज के दौरान मजदूर की मौत होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ। मृतक महाराजपुर के विजय नगर का निवासी था और परिवार में पत्नी साधना व चार बच्चे हैं। मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतक के ससुर शिवभक्त ने आरोप लगाया कि प्रबंधन की लापरवाही और घटना छिपाने की कोशिश के चलते यह हादसा हुआ। परिजनों ने टेनरी संचालक रिजवान के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास का घेराव कर 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की।सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया गैस की चपेट में आने से मौत की बात सामने आई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कड़ाके की ठंड में कक्षा 8 तक के स्कूलों में दो दिन की छुट्टी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जनपद में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिगत अहम निर्णय लिया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में संचालित नर्सरी से कक्षा 8 तक के समस्त बोर्डों के विद्यालयों में 9 व 10 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। सुबह के समय अत्यधिक ठंड एवं कम दृश्यता के कारण विद्यार्थियों को होने वाली संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

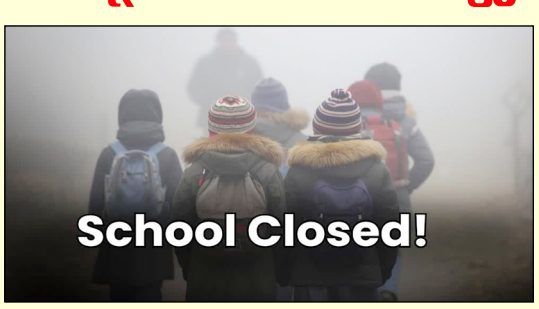

कानपुर में उद्यमियों के लिए खुला पूँजी बाज़ार का रास्ता

एनएसई और उत्तर प्रदेश सरकार की एसएमई आईपीओ कार्यशाला से कारोबार को मिली नई उड़ान

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से कानपुर में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पूँजी बाज़ार से जुड़ने का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 7 जनवरी 2026 को आयोजित एसएमई आईपीओ पर आधारित इंटरैक्टिव कार्यशाला 'कारोबार की उड़ान' ने शहर के उद्यमियों को कारोबार विस्तार के नए अवसरों से रूबरू कराया।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसमें कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, उत्तर प्रदेश सरकार के लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी, ग्राम उद्योग, रेशम उत्पादन और वस्त्र मंत्री राकेश सचान, जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक राज कमल यादव और उद्योग विभाग के आयुक्त एवं निदेशक के. विजयेंद्र पांडियन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यशाला में कानपुर और लखनऊ के चयनित उद्यमियों, वित्तीय विशेषज्ञों और पूँजी बाज़ार से जुड़े पेशेवरों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों को एसएमई आईपीओ के माध्यम से पूँजी जुटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के बारे में जागरूक करना रहा।

सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि यह कार्यशाला कानपुर के लिए ऐतिहासिक पहल है। इससे उद्यमियों को पब्लिक कैपिटल मार्केट की वास्तविक समझ मिलेगी और शहर के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यह कानपुर को औद्योगिक मॉडल शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री राकेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अनेक छोटे उद्योग स्थानीय स्तर पर मजबूत स्थिति में हैं। पूँजी बाज़ार के माध्यम से ये व्यवसाय राष्ट्रीय ब्रांड बन सकते हैं। यह पहल एमएसएमई क्षेत्र के तेज़ और टिकाऊ विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पूँजी बाज़ार को सुलभ बनाना समय की ज़रूरत है। कानपुर जैसे शहरों में अगली पीढ़ी की सूचीबद्ध कंपनियाँ तैयार होने की पूरी क्षमता है। पूँजी बाज़ार दीर्घकालिक निवेश उपलब्ध कराकर व्यवसायों को बड़े स्तर पर विकसित होने में मदद करता है।

एनएसई ने इस आयोजन में सहयोग देने वाले सभी संस्थानों और अचिंत्य सिक्योरिटीज़ के योगदान की सराहना की, जिन्होंने कानपुर के उद्यमी माहौल को सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

आँकड़ों की बात करें तो अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 705 कंपनियाँ एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो चुकी हैं, जिन्होंने 21,489 करोड़ रुपये से अधिक की पूँजी जुटाई है। इनका कुल बाज़ार पूँजीकरण लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश से 71 कंपनियाँ एनएसई में सूचीबद्ध हैं, जिनमें 60 मेनबोर्ड और 11 एसएमई श्रेणी की कंपनियाँ शामिल हैं।

यह कार्यशाला न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता, विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई।

1300 किमी की राष्ट्रवाद साइकिल यात्रा पहुंची कानपुर

महाराजपुर पुलिस ने दिया सुरक्षा प्रोटोकॉल

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । एनसीसी कैडेट्स और सेना के जवानों की 1300 किमी लंबी साइकिल यात्रा कानपुर पहुंची। बिरसा मुंडा के संदेश और राष्ट्रवाद की भावना के साथ यह दल 16 जनवरी को नई दिल्ली में अपनी यात्रा पूर्ण करेगा।रांची से नई दिल्ली के लिए निकली साइकिल यात्रा गुरुवार को महाराजपुर थाना क्षेत्र के कानपुर-फतेहपुर सीमा पर पहुंची। यहां महाराजपुर पुलिस ने प्रोटोकॉल देते हुए यात्रा को सुरक्षित रूप से थाना क्षेत्र पार कराया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एम्बुलेंस भी साथ चल रही थी।

यह ऐतिहासिक यात्रा 28 दिसंबर 2025 को रांची से शुरू हुई थी और 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली पहुंचेगी लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा

में एनसीसी कैडेट्स और सेना के जवान शामिल हैं। उनका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रवाद, एकता और बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान की भावना को फैलाना है।

आयोजकों का कहना है कि इस यात्रा से युवाओं में साहस, अनुशासन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता भी फैलाई जाएगी। यह साइकिल यात्रा न केवल देशभक्ति का संदेश दे रही है, बल्कि बेहतर मानव जीवन और समाज के निर्माण की दिशा में भी प्रेरणा बन रही है।

सम्पादकीय

शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराना अनुचित

हाल के दिनों में देश की शीर्ष अदालत से लेकर आम विमर्श तक में आवारा कुत्तों का मामला सुर्खियों में रहा है। इस संवेदनशील, जटिल व विवादास्पद मुद्दे से जुड़े कई तरह के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बिहार के एक नगर निगम के बेतुके फरमान को लेकर आलोचना की जा रही है। यह निर्णय न केवल बेतुका है बल्कि हास्यास्पद भी है। बिहार के सासाराम के नगर निगम ने शिक्षकों से सड़कों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की गिनती करने को कहा है। दरअसल, अदालत के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों की इस बाबत जवाबदेही तय की गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों व गिरते परीक्षा परिणाम के बावजूद शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर छोटे-बड़े सरकारी अभियान में शिक्षकों की जिम्मेदारी लगाना प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करता है। कभी जनगणना, कभी चुनावी ड्यूटी तो कभी आपदा सर्वेक्षण, और अब कुत्तों की गिनती का बेतुका काम शिक्षकों के जिम्मे लगा दिया गया है। दरअसल, बिहार के शिक्षक विषम परिस्थितियों के चलते पहले ही अत्यधिक दबाव में हैं। जिसके कारण वे शैक्षणिक जिम्मेदारियों व गैर-शिक्षण दायित्वों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हर इस तरह का व्यवधान कक्षा के समय, पाठ योजना और छात्रों की सहभागिता को गहरे तक प्रभावित करता है। निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास की नींव रखती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहता है। वर्षों से पेश की जा रही एएसईआर रिपोर्टों में कई बार उजागर किया गया है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम देश में सबसे कमजोर रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है।ऐसे में जब पहले ही बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है तो शिक्षकों को एक और गैर-शैक्षणिक कार्य के लिये कक्षाओं से बाहर निकालना, निस्संदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह आदेश कई वास्तविक खतरों से भरा है। आवारा कुत्तों की गिनती करना शिक्षण के कागजी कार्य के समान सहज नहीं है। निश्चित रूप से अनेक शिक्षक ऐसे होंगे जो कुत्तों से डरते भी होंगे। खासकर शिक्षिकाओं के लिये यह कार्य खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग इस गणना प्रक्रिया में वास्तविक खतरे का सामना भी कर सकते हैं।

इस बात का संकेत शीर्ष अदालत की टिप्पणी में भी मिलता है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी कुत्ते के मन को पढ़ना या यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई जानवर कब आक्रामक हो जाएगा। निश्चित रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, उनकी सुरक्षा के लिये भी चुनौती होगी। खासकर तब जब आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं और रेबीज से होने वाली जीवन क्षति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम के आदेश की तार्किकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण और जन सुरक्षा उपायों को लागू करने में नगरपालिकाओं की विफलता पर सवाल उठाए थे।

उम्मीद के जुगनुओं का आभास देता साहस

यशवंत सचदेव

जनतंत्र में पत्रकारिता भय के नहीं, सत्य के प्रति उत्तरदायी होती है। सत्य को समाज के सामने रखना और सत्य के पक्ष में खड़ा होते हुए दिखना पत्रकारिता का धर्म है। तभी उसकी विश्वसनीयता बनी रह सकती है। यह विश्वसनीयता... जनतंत्र में पत्रकारिता भय के नहीं, सत्य के प्रति उत्तरदायी होती है। सत्य को समाज के सामने रखना और सत्य के पक्ष में खड़ा होते हुए दिखना पत्रकारिता का धर्म है। तभी उसकी विश्वसनीयता बनी रह सकती है। यह विश्वसनीयता पत्रकारिता का प्राण-तत्व है।देश के सबसे स्वच्छ माने जाने वाले शहर इंदौर में पीने के दूषित पानी के कारण चौदह लोग मारे गये और दो सौ से अधिक लोग बीमार होकर अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। मरने वालों और बीमार होने वालों की यह संख्या एक आंकड़ा मात्र नहीं है

प्रशासन और संबंधित मंत्री महोदय ने पीड़ितों की सहायता और स्थिति को सुधारने का आश्वासन दिया है। मामला गंभीर है और अपनी तरह का पहला कांड भी नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह की आपराधिक लापरवाही के उदाहरण अक्सर मिलते रहते हैं। इस मामले में राज्य के संबंधित मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपना 'अपराध' भी स्वीकार किया है और खेद भी व्यक्त किया है। अब मामले की जांच होगी, कुछ कार्रवाई भी होगी। और फिर इसे भी पहले की ऐसी वारदातों की तरह भुला दिया जायेगा, आवश्यकता भूल जाने की इस प्रवृत्ति से निपटने की है। यह याद रखा जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्तियों-विभागों की लापरवाही के कारण इतना गंभीर कांड हो गया, जो किसी भी दृष्टि से क्षम्य नहीं है। लेकिन इस त्रासदी के साथ जुड़े दो पक्ष और भी हैं, जिन्हें याद रखा जाना चाहिएङ्क पहले तो यह कि इस कांड के दौरान देश ने अपने एक बड़े माने जाने वाले नेता की उथली सोच और व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया है और दूसरा पक्ष उस एक पत्रकार के व्यवहार वाला है, जिसने मंत्री महोदय के घटिया उद्गारों का तत्काल विरोध किया। जहां अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री, क्षमा मांगने के बावजूद लोक-मर्यादा के कटघरे में खड़े हैं, वहीं उस पत्रकार की सब प्रशंसा कर रहे हैं, जिसने पूरी गंभीरता और साहस के साथ मंत्री महोदय को यह जता दिया कि उनका व्यवहार अशोभनीय ही नहीं, शर्मनाक भी था। यह बात क्षमा मांग कर रफा-दफा करने की नहीं है, अपना आपा खोने वाले ऐसे मंत्री को इतने ज़िम्मेदार पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्रशंसा उस पत्रकार की होनी चाहिए, जिसने इस कांड में पूरे साहस और निर्भीकता के साथ मंत्री महोदय को उनकी औकात दिखाई। घटना के वीडियो वायरल हो जाने वाले इस समय में कोई यह कहकर बच नहीं सकता कि उसने ऐसा नहीं कहा था अथवा उसे ग़लत उद्धृत किया जा रहा है। सब कुछ सबके सामने आ जाता है। इंदौर के इस कांड में स्पष्ट दिख रहा है कि मंत्री जी ने पत्रकार के वाजिब और ज़रूरी सवाल को सिर्फ 'फोकट' का प्रश्न ही नहीं बताया बल्कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो सभ्य समाज में अभद्र माना जाता है। लेकिन इस मामले में प्रशंसनीय बात पत्रकार अनुराग द्वारी का साहस है जो उन्होंने मंत्री महोदय के सामने प्रकट किया। प्रशंसनीय इसलिए कि हमारे आज के दौर में किसी पत्रकार का इस तरह का साहस दिखाना अपने आप में एक समाचार है। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी आज की पत्रकारिता पर सत्ता के समक्ष झुकने के आरोप आये दिन लग रहे हैं और इसके उदाहरण भी अक्सर मिलते रहते हैं। यही नहीं, मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से की तो पहचान ही 'गोदी मीडिया' वाली हो गयी हैङ्कगोदी मीडिया यानी सत्ता के समक्ष नतमस्तक पत्रकारिता।

कर वसूली के साथ जरूरी सुविधाएं भी तो मिलें

जनोन्मुखी टैक्स व्यवस्था

डा0 सुधीर कुमार

देश में दोहरी कर प्रणाली आम नागरिक के लिए असंतोष का कारण बन रही है। पहले वेतन पर आयकर और फिर खर्च पर जीएसटी। यह भी कि सत्ताधारी लोग सुविधाओं में जीते हैं और आम नागरिक मूल जरूरतों के लिए जूझते हैं। कर ढांचा न्याय व समानता पर आधारित होना चाहिए।भारत का आम नागरिक आज कर व्यवस्था को लेकर गहरे असमंजस में है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसके लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है। राष्ट्र निर्माण का दायित्व निभाने वाला यही वर्ग सबसे अधिक दबाव में है। इस असंतोष की जड़ में वह संरचना है जिसे आम भाषा में दोहरी कर व्यवस्था कहा जाता है।

कागजों में यह व्यवस्था तर्कसंगत दिखाई देती है। लेकिन धरातल पर यही व्यवस्था नागरिक की जेब और विश्वास दोनों पर चोट करती है।

एक नागरिक महीने भर श्रम करता है। वेतन पाता है। उसी वेतन पर वह आयकर देता है। लेकिन कर यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कर कटने के बाद बची हुई आय से जब वह दवा खरीदता है। भोजन करता है। ईंधन भरवाता है। बच्चों की शिक्षा या किसी सेवा का भुगतान करता है तो हर कदम पर उसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देना पड़ता है। सरकार का तर्क है कि आयकर कमाने पर है और जीएसटी व्यय पर। तकनीकी रूप से यह बात सही हो सकती है। लेकिन आम नागरिक के लिए आय का स्रोत एक ही होता है और खर्च भी उसी सीमित राशि से होता है। पैसा वही रहता है। केवल कर के नाम बदल

जाते हैं। बोझ कम नहीं होता।

यह पीड़ा तब और गहरी हो जाती है जब नागरिक सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों की जीवनशैली देखता है। प्रश्न तब केवल कानूनी नहीं रह जाता बल्कि नैतिक हो जाता है। आम नागरिक पूछता है कि जब उसने अपनी आय पर कर चुका दिया तो जीवन की हर जरूरत पर दोबारा कर क्यों? लोकतंत्र में इस प्रश्न को असंगत नहीं कहा जा सकता।कानूनी सच्चाई यह है कि सांसदों और विधायकों का वेतन आयकर के दायरे में आता है और वे कर देते हैं। लेकिन असमानता वेतन में नहीं बल्कि सुविधाओं में है। सरकारी आवास, बिजली- पानी, यात्रा, चिकित्सा, सुरक्षा व स्टाफ जैसी सभी सुविधाओं का बाजार मूल्य अत्यंत ऊंचा है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को यह या तो मुफ्त मिलता है या नाममात्र शुल्क पर।

इस असंतुलन को और उजागर करती है उद्घाटन और दौरों की संस्कृति। मामूली से कार्यक्रम के लिए भी नेता विमान या हेलिकॉप्टर से पहुंचते हैं। सुरक्षा के नाम पर लंबे काफिले चलते हैं। सड़कें रोकी जाती हैं। प्रशासनिक तंत्र उसी आयोजन में झोंक दिया जाता है। इन सब पर होने वाला खर्च लाखों और कई बार करोड़ों में होता है। यह खर्च देश के राजस्व से होता है। यानी उसी करदाता के पैसे से जो स्वयं यातायात में फंसा हुआ अपने ईंधन का पूरा मूल्य और कर चुका रहा होता है।

कृषि आय को कर से मुक्त रखने का निर्णय अपने समय में मानवीय और आवश्यक था। खेती जोखिम भरा और मौसम पर निर्भर है। छोटे किसान की आय अस्थिर होती है। लेकिन समय के साथ इस छूट का दुरुपयोग भी बढ़ा। अनेक गैर किसान और प्रभावशाली लोग अपनी आय को कृषि आय दिखाकर टैक्स से बचते रहे। असली किसान तक इस व्यवस्था का कितना लाभ पहुंचा यह आज भी स्पष्ट नहीं। इससे कर व्यवस्था के प्रति अविश्वास और गहराता है।मूल प्रश्न इससे भी आगे का है। जब नागरिक कर देता है तो बदले में उसे क्या मिलता है। शिक्षा आज भी निजी संस्थानों पर निर्भर है। स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं। वृद्धावस्था की सुरक्षा सीमित है। रोजगार अनिश्चित है। कर चुकाने के बाद भी जीवन की बुनियादी जिम्मेदारियां नागरिक को स्वयं उठानी पड़ती हैं। ऐसे में कर राष्ट्र निर्माण की साझेदारी नहीं बल्कि मजबूरी जैसा लगने लगता है।

जूट गोदाम में भीषण आग

6 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

❍ 50 लाख का माल स्वाहा, साजिश की आशंका ❍ बिक्री के रखे 27 हजार भी जलकर राख

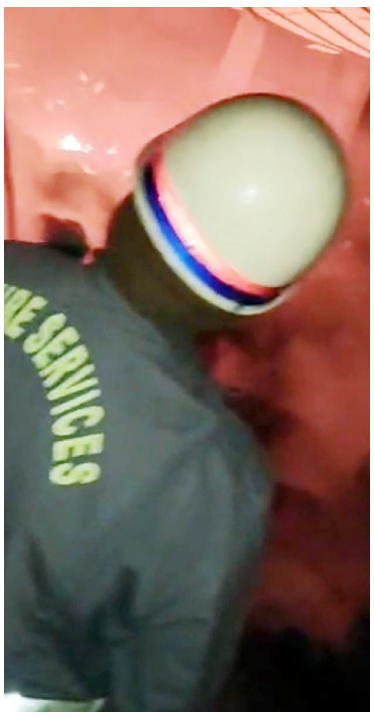

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

चौबेपुर (कानपुर नगर)। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गोगूमऊ गांव में बुधवार रात शुभम ट्रेडर्स के जूट गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना के समय गोदाम के बाहर बने ऑफिस में आराम कर रहे कर्मचारी कानपुर निवासी सुद्दू और धर्मेंद्र ने गोदाम से धुआं उठता देखा। दोनों कर्मचारियों ने अंदर जाकर देखा तो गोदाम में आग लगी हुई थी।

आग की जानकारी मिलते ही धर्मेंद्र ने गोदाम मालिक राजू को फोन कर सूचना दी। सूचना पर मालिक मौके पर पहुंचे, वहीं थोड़ी ही देर में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद एक के बाद एक करीब छह दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। घंटो मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि गोदाम में रखा जूट का माल जलने से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

बिजली कनेक्शन नहीं साजिश की आशंका

गोदाम में आग कैसे लगी, इसका कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। गोदाम मालिक ने बताया कि गोदाम में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। वहां लगे सोलर पैनल भी लंबे समय से डाउन हैं, हालांकि सर्दी के बावजूद बुधवार को धूप निकलने से थोड़ा-बहुत चार्ज हुआ था। गोदाम मालिक का कहना है कि इस स्थिति में आग लगना समझ से परे है, जिससे किसी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने फिलहाल किसी व्यक्ति पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया है। बताया कि लोग कह रहे हैं तुम्हारे साथ गेम हो गया।

9 बजे मिली आग की सूचना, 50 लाख का नुकसान

स्वराज इंडिया से बात करते हुए शुभम ट्रेडर्स के मालिक राजू राठौर ने बताया कि वह रोज की तरह बुधवार शाम करीब 7:30 बजे गोदाम बंद कर घर चले गए थे। गोदाम की देखरेख के लिए ऑफिस में दो कर्मचारी मौजूद रहते हैं। रात करीब 9 बजे कर्मचारी धर्मेंद्र ने फोन कर गोदाम में आग लगने की सूचना दी। राजू राठौर के अनुसार आग की चपेट में आकर करीब 50 लाख रुपये का जूट का माल जल गया, जबकि गुल्लक में रखे 27 हजार रुपये नकद भी आग में खाक हो गए। उन्होंने बताया कि आग लगने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग अभी भी पूरी तरह नहीं बुझी है।

नाबालिग को फुसला कर ले जाना वाला आरोपी गिरफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। नाबालिग को फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया। इस संबंध में बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 21 नवंबर 2025 को थाने में मामला दर्ज कराया था।

दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उनकी करीब 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को फुसलाकर कहीं ले जाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई है। टीम ने नानामऊ अंडरपास बाईपास, थाना बिल्हौर क्षेत्र से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मौके से अजय कुमार, निवासी जीयनखेड़ा, थाना आसीवन, जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस में आरोपी से पूछताछ के बाद को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया।

कड़ाके की ठंड में समाजवादियों की मानवीय पहल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते समाजवादी पार्टी की ओर से मानवीय पहल की गई। बिल्हौर ब्लॉक के मकनपुर कस्बे निवासी समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष मुकीम खान के नेतृत्व में कस्बे के प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर जगह-जगह अलाव जलवाए गए, जिससे राहगीरों, मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत मिली। स्थानीय नागरिकों ने समाजवादी पार्टी की इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित में सराहनीय कदम बताया।

कंबल न मिलने पर भड़के किसान, तहसील में दिया धरना

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- किसान नेता का आरोप, अधिकारी गोलमोल जवाब देकर टाल रहे जिम्मेदारी
- एसडीएम बोले लिस्ट को जाँच कर पात्रों को दिया जाएगा कंबल

बिल्हौर (कानपुर नगर)। कड़ाके की ठंड के बावजूद जरूरतमंद किसानों को कंबल न मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन की जिलाध्यक्ष रजनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान तहसील परिसर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अपनी बात कहेंगे।

किसानों ने बताया कि करीब डेढ़ सौ जरूरतमंद किसानों की सूची पूर्व में ही तहसील प्रशासन को सौंप दी गई थी। इसके बाद किसानों को कंबल वितरण के नाम पर तहसील बुलाया गया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आरोप है कि तहसील स्तर के अधिकारियों से कई बार बातचीत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया।

किसानों का कहना है कि अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि लेखपालों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कंबल वितरित कर दिए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि कई जरूरतमंद किसान अब भी कंबल से वंचित हैं। इससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उधर, धरने की सूचना पर खुफिया विभाग के अधिकारी ए.के. सिंह मौके पर पहुंचे। किसानों ने उन्हें घेर लिया और अपनी समस्या से अवगत कराया। इस पर खुफिया विभाग के अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे परेशान न हों और कंबल वितरण से जुड़े पूरे मामले से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण गरीब और जरूरतमंद किसान ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। मैंने किसानों की सूची बनाकर अधिकारियों को दी थी।तहसील बुलाया गया, लेकिन कंबल न देकर अधिकारी सिर्फ गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अन्नदाता को क्या इस तरह से परेशान किया जाएगा। शीघ्र सभी पात्र किसानों को कंबल नहीं दिए गए तो संगठन आगे की रणनीति तैयार करेगा। किसानों की और भी कई समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया है।

रजनी सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन

कंबल हर पात्र को मिल रहा है किसानों द्वारा दी गई सूची में कई नाम ऐसे हैं जो कंबल पाने के लिए पात्र नहीं हैं। पात्र लोगों की जांच कर चिन्हांकन किया जा रहा है और जल्द ही वास्तविक जरूरतमंद किसानों को कंबल वितरित कर दिए जाएंगे।

डॉ संजीव कुमार दीक्षित, उपजिलाधिकारी, बिल्हौर

एसआईआर से बदल गया यूपी का सियासी गणित !

यूपी की राजनीति में शहरी बनाम ग्रामीण संतुलन को नए सिरे से परिभाषित किया गया

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 2.89 करोड़ नाम कटे, शहरी गढ़ों में सबसे बड़ा झटका

अनूप अवस्थी स्वराज इंडिया

स्वराज इंडिया - स्पेशल रिपोर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) ने प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। चार नवंबर से 26 दिसंबर तक चले इस अभियान में मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता सूची से दो करोड़ 89 लाख नाम कट गए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 44 लाख से घटकर 12 करोड़ 55 लाख रह गई है।

सबसे बड़ा असर शहरी इलाकों में देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में जहां पहले 39 लाख 90 हजार मतदाता थे, अब उनकी संख्या घटकर 27 लाख 90 हजार रह गई है, यानी 30 प्रतिशत से अधिक कटौती। इसी तरह गाजियाबाद में 8.18 लाख (29त्न), प्रयागराज में 11.56 लाख, कानपुर में 9 लाख और आगरा में 8.36 लाख नाम सूची से हटे हैं। आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि प्रवासी मजदूरों, नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के शहरी मतदाताओं पर अभियान का सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

भाजपा को लखनऊ, गाजियाबाद जैसे शहरी संसदीय क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ का भरोसा था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। विपक्ष का दावा है कि कटे नामों में 80 से 90 प्रतिशत भाजपा समर्थक हो सकते हैं।

हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और सांसदों के साथ वर्चुअल बैठकें कीं। संगठन स्तर पर भी सक्रियता बढ़ाई गई और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत कार्यक्रमों तक स्थगित कर मतदाता सूची पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। संघङ्कसंगठन की बैठकों में भी यह मुद्दा प्रमुख रहा कि बूथ स्तर पर लापरवाही के कारण समय रहते फॉर्म भरवाने और समस्याएं सुलझाने का काम नहीं हो पाया।विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने यूपी की राजनीति में शहरी बनाम ग्रामीण संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। जहां भाजपा के शहरी गढ़ कमजोर हुए हैं, वहीं सपा को ग्रामीण आधार से मजबूती मिली है। बसपा को सीमित लाभ और शहरी नुकसान, जबकि कांग्रेस को सबसे अधिक क्षति झेलनी पड़ी है। आने वाले चुनावों में यह बदलाव निर्णायक साबित हो सकता है।

सपा की सक्रियता, ग्रामीण आधार मजबूत

इसके उलट समाजवादी पार्टी ने अभियान के दौरान आक्रामक रणनीति अपनाई। पार्टी ने कैम्प लगाकर फॉर्म भरवाए, बूथवार सत्यापन किया और ड्राफ्ट सूची की प्रतियां हासिल कीं। कानपुर और अमेठी जैसे जिलों में सपा की सक्रियता का असर यह रहा कि उसके वोटरों के नाम अपेक्षाकृत कम कटे। सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान का दावा है कि जहां भाजपा को शहरी इलाकों में नुकसान होगा, वहीं सपा का वोट ग्रामीण क्षेत्रों में और मजबूत होकर उभरेगा।

बसपा और कांग्रेस पर मिला-जुला असर

बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में नाम कटौती अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन आगरा और लखनऊ जैसी शहरी सीटों में 25-30 प्रतिशत कटौती से पार्टी के वोट शेयर पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि डुप्लीकेट और मृत नाम हटने से सूची के शुद्ध होने को बसपा दीर्घकालिक लाभ के रूप में देख रही है।

वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान शहरी गरीब और अल्पसंख्यक वोट बैंक से हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रक्रिया को जल्दबाजी वाला बताया, जबकि वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया।

आगे की लड़ाई 6 फरवरी तक

अब छह फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। सभी राजनीतिक दल इस चरण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि कटे नाम कितनी संख्या में वापस जुड़ते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि लखनऊ में 12 लाख नाम कटने से प्रति विधानसभा 60 से 80 हजार वोट कम हुए हैं, जिससे 10 से 15 सीटों का समीकरण बदल सकता है।

कानपुर में मेहनाज़ ज्वैलर्स बाय कांडा ब्रदर्स का भव्य शुभारंभ

» उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की बेटी एवं अभिनेत्री टीना आहूजा रहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। किदवई नगर क्षेत्र में मेहनाज़ ज्वैलर्स बाय कांडा ब्रदर्स रिटेल ज्वैलरी शोरूम का भव्य उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह नया ज्वैलरी शोरूम 128/1, सी-ब्लॉक, हनुमान मंदिर के पास, किदवई नगर, कानपुर-208011 में स्थित है।

उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की बेटी एवं अभिनेत्री टीना आहूजा रहीं। उन्होंने विधिवत रूप से फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। उनकी मौजूदगी से कार्यक्रम में विशेष आकर्षण बना रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने इस अवसर में सहभागिता की।इस मौके पर शोरूम के निदेशक साहिब सिंह, निदेशक जसनप्रीत सिंह तथा मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ करणजीत सिंह उपस्थित रहे। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि मेहनाज़ ज्वैलर्स का उद्देश्य ग्राहकों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधुनिक सुविधाओं के साथ एक भरोसेमंद ज्वैलरी अनुभव प्रदान करना है।शोरूम में सोना, डायमंड एवं चांदी के आभूषणों का आकर्षक कलेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इसमें पारंपरिक डिज़ाइन, ब्राइडल ज्वैलरी और आधुनिक शैली के आभूषणों की विशेष रेंज शामिल है, जो हर वर्ग के ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।उद्घाटन समारोह में शहर के गणमान्य नागरिकों, व्यापार जगत से जुड़े लोगों तथा मीडिया प्रतिनिधियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। नए शोरूम के शुभारंभ से क्षेत्र में ज्वैलरी व्यापार को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

लाखों हो गए खर्च, फिर भी कागजों में ही चल रहा सामुदायिक शौचालय

अफसरों की चुप्पी पर उठे सवाल, पंचायत विभाग जनता की समस्या सुलझाने में नाकाम

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अकबरपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत पातेपुर में लाखों रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए चलाई जा रही योजनाएं जमीनी स्तर पर दम तोड़ती दिख रही हैं, जबकि पंचायत विभाग के अधिकारी मामले को गंभीरता से लेने के बजाय अनदेखी कर रहे हैं। केवल कागजों में ही इस शौचालय का संचालन होना दिखाया जा रहा है।

स्वराज इंडिया

कानपुर देहात

हद है: एडीओ पंचायत की भी नहीं सुन रहे ग्राम पंचायत सचिव

» अखबारों में छपने के बाद भी नहीं ध्यान नहीं दे रहे जिम्मेदार

» अभी तक नहीं हो सका सामुदायिक शौचालय का पुनः संचालन

FOLLOW UP

जब स्वराज इंडिया ने पहली बार इस मुद्दे को उजागर किया था, तब प्रशासन हरकत में आया और जांच का आश्वासन एडीओ पंचायत द्वारा दिया गया था। लेकिन समय बीतने के साथ यह साफ होता जा रहा है कि पूरे प्रकरण में पंचायत विभाग की मनमानी हावी है और जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआत में कुछ समय के लिए सामुदायिक शौचालय का संचालन हुआ, लेकिन उसके बाद से आज तक ताले ही लटके हुए हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो संचालन शुरू कराया गया और न ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हुई। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद भी अधिकारियों की उदासीनता सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूरी की जा रही है, जिससे खुलेआम भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है।शौचालय बंद रहने के कारण ग्रामीणों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे स्वच्छता अभियान की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और गांव में बीमारियों के फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि आखिर कब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और कब जनता को इस बुनियादी सुविधा का वास्तविक लाभ मिलेगा।

क्या बोले जिला पंचायत राज अधिकारी...

डीपीआरओ विकास पटेल ने बताया है कि मामले की जानकारी नहीं है आपके माध्यम से सामुदायिक शौचालय संचालन न होने की जानकारी मिली है तत्काल अभी सचिव और प्रधान को निर्देशित किया जा रहा है हर हाल मे उसको मरम्मत कराकर संचालन कराया जायेगा।

अवैध खनन में लगी जेसीबी को पकड़ा बाकी भागे

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिवली थाना के अरशदपुर गांव के पास अवैध खनन पर तहसील प्रशासन ने छापेमारी की। छापेमारी में एक जेसीबी पुलिस ने पकड़ी है। जब कि खनन में लगे लोग डंपर ट्रैक्टर लेकर भाग निकले।

कई दिनों से अरशदपुर गांव के समीप अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। इसी उसमें नायब तहसीलदार अनिरुद्ध कुमार व थाना प्रभारी शिवली प्रवीण कुमार यादव ने छापेमारी की। खनन में लगी जेसीबी को मौके पर पकड़ लिया गया। जब कि खनन में लगे लोग भाग निकले। नायब तहसीलदार ने बताया कि लेखपाल को स्थलीय जांच हेतु निर्देशित किया गया है। कि इंस्पेक्टर का कहना है कि जेसीबी सीज की जाएगी। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी।

महिला सिपाही पर्स लूट कांड का आरोपी बोला, माफ कर दो गलती हो गई

» एनकाउंटर के डर से दूसरे आरोपी ने सीसामऊ थाने में किया आत्मसमर्पण

» शराब के नशे में रची थी लूट की साजिश, दोनों आरोपी भेजे गए जेल

»प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर।गांधी नगर में महिला सिपाही का पर्स लूटने के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपित ने पुलिस एनकाउंटर के डर से आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। बजरिया के बेकनगंज निवासी शयान रजा उर्फ शयान मिर्जा ने बुधवार को सीसामऊ थाने में सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उसे लगभग एक किलोमीटर तक मुहल्ले में कान पकड़कर जुलूस निकलवाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जुलूस के दौरान एक दरोगा द्वारा सख्त लहजे में दोबारा अपराध न करने की चेतावनी देने पर आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा। उसने कहा कि अब वह ऐसी गलती नहीं करेगा और कानपुर छोड़कर मुंबई चला जाएगा। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

घटना 28 दिसंबर की सुबह की है। चमनगंज थाने परिसर स्थित आवास में रहने वाली महिला सिपाही पिंकी पाल, जो महिला थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ड्यूटी के बाद घर लौट रही थीं। पी रोड पर ऑटो से उतरकर गांधी नगर की ओर पैदल जाते समय स्कूटर सवार दो युवकों ने उनका पर्स लूट लिया था। पर्स में 10 हजार रुपये, ब्लूटूथ डिवाइस और जरूरी दस्तावेज थे।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पहले एक आरोपित मारूफ (निवासी कंघी मोहाल) को प्रेम नगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दूसरा आरोपी शयान रजा फरार चल रहा था। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि शयान को जानकारी मिली थी कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के दौरान सख्त कार्रवाई कर सकती है,

इसी डर से वह फतेहपुर से अपने दोस्त और परिजनों के साथ थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण किया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपितों ने 27 दिसंबर की रात शराब पी थी। पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने लूट की योजना बनाई और महिला सिपाही को निशाना बनाया। मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 l **Email:** swarajindia2023@gmail.com l **Mob:** 7800009853, l **Website:** www.swarajindianews.com l **(समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)** प्रादेशिक कार्यालय:4ए/5,119/10बी, खान बिल्डिंग, पार्क रोड हजरतगंज

साहब, कड़ाके की ठंड में पशु आश्रय स्थलों को नहीं देख रहा कोई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच जहां आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं जनपद के पशु आश्रय स्थलों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। अधिकांश पशु आश्रय स्थलों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। जिम्मेदारों का कहना है कि बीते लगभग दो माह से बजट न आने के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित रहीं, हालांकि हाल ही में पशु आश्रय स्थलों का मासिक भुगतान जारी किया गया है।

न अलाव की व्यवस्था, न काऊ कोट, प्रधान बोले चार माह से बजट नहीं आया था, जिससे दिक्कतें हुईं

रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत लालाभगत ग्राम पंचायत में संचालित पशु आश्रय स्थल की जमीनी हकीकत प्रशासनिक दावों की पोल खोलती नजर आई। यहां न तो पशुओं को ठंड से बचाने के लिए काऊ कोट उपलब्ध थे और न ही पर्याप्त चारे की व्यवस्था दिखाई दी। पशुओं के लिए अलाव जलाने के बजाय केयरटेकर स्वयं पशु आहार स्थल के बाहर अलाव तापते नजर आए।

जिले के आला अधिकारी भले ही पशु आश्रय स्थलों में बेहतर व्यवस्थाओं के दावे कर रहे हों, लेकिन स्थलीय निरीक्षण में हालात इसके बिल्कुल विपरीत पाए गए। पशुओं को न तो पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है और न ही उन्हें ठंड से बचाने की उचित व्यवस्था की गई है। सुविधाओं के अभाव में कई पशुओं के दम तोड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

ग्राम प्रधान ने दी सफाई

इस संबंध में लालाभगत ग्राम प्रधान प्रदीप पाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि काऊ कोट उपलब्ध हैं और पशुओं को पहनाए जा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि बीते चार माह से गौशाला का बजट नहीं आया था, जिससे दिक्कतें हुईं। हालांकि अब दो माह का भुगतान प्राप्त हो गया है और शीघ्र ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा।

कलेक्ट्रेट में डीएम ने की जनसुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों को दिए निर्देश

» प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में डीएम कपिल सिंह द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने जनसामान्य की विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। शिकायतकर्ताओं को निस्तारण की प्रगति एवं स्थिति से समय-समय पर बताया जाए।

इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा एक नई पहल के तहत जनसुनवाई में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जनशिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए शासन की मंशा के अनुरूप त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) दिग्विजय सिंह सहित अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बाइक सवार को बचाने में ऑटो पलटा, एक घायल

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट जाने के चलते उसमें सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल देवराहट के बमरौली घाट निवासी 40 वर्षीय अशोक कुमार गुप्ता को उपचार के लिए पुखरायां सीएचसी में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा पटेल चौक के निकट एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ।

शीतलहर में इंसानियत की गर्माहट नजर आई

लाइफ इंस्पायरिंग फ़ाउंडेशन का कंबल वितरण अभियान जारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों के लिए राहत बनकर उभरी है लाइफ इंस्पायरिंग फ़ाउंडेशन (लाइफ एनजीओ)। संस्था द्वारा 24 दिसंबर 2025 से पुखरायाँ, भोगनीपुर और आसपास के क्षेत्रों में निरंतर कंबल वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बेसहारा लोगों, बुजुर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सर्दी से बचाव का सहारा मिल रहा है।अभियान का विशेष फोकस उन वर्गों पर है जो शीतलहर में सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं—बेघर लोग, दिहाड़ी मजदूर, वृद्धजन और असहाय नागरिक। ठिठुरन भरी रातों में कंबल मिलने से लाभार्थियों के चेहरों पर राहत और सुरक्षा की झलक साफ दिखाई देती है।

लाइफ एनजीओ के समर्पित स्वयंसेवकों ने विभिन्न इलाकों में पहुँचकर वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान की और उन्हें सम्मानपूर्वक कंबल वितरित किए। संस्था का मानना है कि सेवा केवल सामग्री वितरण तक सीमित नहीं, बल्कि करुणा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं को सशक्त करने का माध्यम है।संस्था के

प्रतिनिधि अंकित सिंह और दानिश सिद्दिकी ने बताया कि जब तक ठंड का प्रकोप रहेगा, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने समाज के सक्षम नागरिकों से इस मानवीय पहल में सहयोग करने की अपील भी की।

स्थानीय नागरिकों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान न केवल तत्काल राहत देते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और आपसी सहयोग की भावना को भी मजबूत करते हैं। शीतलहर के बीच लाइफ इंस्पायरिंग फ़ाउंडेशन की यह मुहिम उम्मीद, संवेदना और इंसानियत की गर्माहट का संदेश बनकर सामने आई है।

कालिका प्रसाद मिश्रा बने अधिवक्ता संघ अयोध्या के अध्यक्ष

» उपाध्यक्ष से मंत्री तक, कड़ा रहा मुकाबला

» कोषाध्यक्ष और संयुक्त मंत्रियों में भी रोचक चुनाव

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अधिवक्ता संघ अयोध्या का बहुप्रतीक्षित चुनाव आखिरकार शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो गया। पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर कालिका प्रसाद मिश्रा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सूर्यभान वर्मा को 312 मतों से पराजित किया। कालिका प्रसाद मिश्रा को कुल 1150 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सूर्यभान वर्मा को 848 मतों से संतोष करना पड़ा।

उपाध्यक्ष पद पर राजेश उपाध्याय ने जीत हासिल की। संघ के दूसरे सबसे अहम मंत्री पद पर शैलेन्द्र कुमार जायसवाल ने 763 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय श्रीवास्तव को 242 मतों से पराजित किया।

मंत्री पद के अन्य प्रत्याशियों में प्रदीप कुमार चौबे को 396, राजेश कुमार यादव को 210, विनोद कुमार सिंह को 106, योगेंद्र प्रसाद पांडे को 97, श्री प्रकाश दुबे को 18 मत मिले, जबकि 13 मत अवैध घोषित किए गए।कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार दुबे ने 904 मत पाकर जय प्रकाश पाल को 184 मतों से पराजित किया। जय प्रकाश पाल को 720, राजेंद्र प्रसाद तिवारी को 378 और महेंद्र प्रसाद तिवारी को 173 मत प्राप्त हुए।

संयुक्त मंत्री प्रथम पद पर मनोज कुमार सिंह ने 1177 मत प्राप्त कर संतोष कुमार मिश्रा (1049 मत) को 128 मतों से हराया। इस पद पर 47 मत अवैध घोषित हुए।

संयुक्त मंत्री द्वितीय पद पर पियूषमय त्रिपाठी ने अखंड प्रताप यादव को कांटे के मुकाबले में 47 मतों से पराजित किया। पियूषमय त्रिपाठी को 893 और अखंड प्रताप यादव को 847 मत मिले, जबकि 55 मत अवैध रहे।

कार्यकारिणी में इन प्रत्याशियों का चला जादू

कार्यकारिणी ए - पंकज कुमार द्विवेदी (924 मत) और दुर्गा प्रसाद सिंह (779 मत) विजयी

कार्यकारिणी बी- अभय प्रताप सिंह (911 मत) और बद्री प्रसाद यादव (900 मत) विजयी

कार्यकारिणी सी - रुद्र प्रकाश मिश्रा (777 मत) और अमित वर्मा (688 मत) विजयी कार्यकारिणी के कुल 28 मत अवैध घोषित किए गए।

चुनाव अधिकारी सूर्यनारायण सिंह ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह ने कहा कि अधिवक्ता संघ का चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने मतदान में भाग लेने वाल अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। अधिवक्ता संघ चुनाव के नतीजों के साथ ही अब संघ की नई कार्यकारिणी से अधिवक्ताओं के हितों को लेकर मजबूत और प्रभावी भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है।

सपा विधायक व कद्दावर नेता विजय सिंह गोंड का निधन

» लखनऊ में लंबे समय से चल रहा था इलाज, किडनी खराब हो गई थी

» कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव में मिली थी जीत

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के दुद्धी क्षेत्र के विधायक विजय सिंह गोंड का लखनऊ के एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान निधन हुआ। उनके निधन की पुष्टि पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अवधनारायण यादव ने की। लंबे समय से बीमार चल रहे विजय सिंह गोंड की दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था।आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करने वाले

प्रदेश की 403वीं अंतिम विधान सभा सीट दुद्धी के आदिवासी राजनीति के 'पितामह' कहे जाने वाले गोंड के निधन से पूरे सोनभद्र और आस-पास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। विजय सिंह गोंड आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करने वाले अग्रणी नेताओं में शुमार थे। दुद्धी और ओबरा विधानसभा को अनुसूचित जनजाति सीट घोषित कराने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। वनवासी सेवा आश्रम में मात्र 200 रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने 1979 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

आठ बार रहे विधानसभा के सदस्य

1989 में अपने राजनीतिक गुरु रामप्यारे पनिका को हराकर उन्होंने आदिवासी राजनीति में नया अध्याय लिख दिया। विभिन्न दलों से होते हुए वे आठ बार विधानसभा के सदस्य रहे और प्रदेश की राजनीति में आदिवासी हितों को नई पहचान दिलाई। गोंड ने सदन में आदिवासी समाज के अधिकारों को मजबूती से उठाया और उन्हें मुख्यधारा में लाने का उल्लेखनीय प्रयास किया। विजय सिंह गोंड के निधन से राजनीतिक, सामाजिक और आदिवासी समुदाय में गहरा शोक व्याप्त है। नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उनके निधन को अपूरणीय क्षति मान रहे हैं।

परिषदीय स्कूलों में बड़ी कार्रवाई, 10 की सेवा समाप्त, एक शिक्षिका निलंबित

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अलीगढ़।बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए नौ शिक्षकों और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि एक सहायक अध्यापिका को निलंबित किया गया है।

वर्षों से गैरहाजिर शिक्षकों पर गिरी गाज, बीएसए के निर्देश पर एक्शन, हस्ताक्षर कर स्कूल से गायब मिली शिक्षिका निलंबित, अनुशासनहीनता पर सख्ती

अलीगढ़ के बीएसए डॉ. राकेश सिंह के अनुसार, 22 जुलाई 2025 को जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) से ऐसे प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों और कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी गई थी, जो लंबे समय से विद्यालयों में अनुपस्थित चल रहे थे। बीईओ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बीईओ बिजौली की रिपोर्ट में प्राथमिक विद्यालय बडेसरा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वर्ष 2021 से अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय बढ़ेपुरा की सहायक अध्यापिका अनुराधा 2019 से और विकास शर्मा मई 2024 से गैरहाजिर पाए गए।

इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय नगला कामसहाय के सहायक अध्यापक विकास तोमर मई 2023 से, नगला बंजारा की सहायक अध्यापिका निकिता गुप्ता मार्च 2021 से, नगर क्षेत्र के बालक पाठशाला संख्या-14 की

सहायक अध्यापिका शबाना रिजवी जून 2022 से, अकराबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय हिरनपुरा की शुभी वार्ष्णेय फरवरी 2024 से, प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर की कंचन गौतम मई 2020 से, गंगीरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगला जाटवान के इमरान अली जनवरी 2025 से तथा गौंडा ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल बासटोडा के हरेंद्र कुमार सितंबर 2019 से लगातार अनुपस्थित पाए गए। बीएसए ने बताया कि विभाग ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई की।

वहीं गौंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुड़िया में 24 दिसंबर 2025 को बीईओ द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में सहायक अध्यापिका संगम यादव हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित मिलीं। इससे पूर्व भी वह 3, 5 और 13 दिसंबर को अनुपस्थित पाई गई थीं। बार-बार गैरहाजिरी के बावजूद बाद में चिकित्सा अवकाश का आवेदन देना लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

अयोध्या में बिजली व्यवस्था की बदल गई सूरत

वर्टिकल सिस्टम लागू, 4 हेल्पडेस्क भी किए जाएंगे सक्रिय: निदेशक

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के शहरी क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा नई वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है। यह जानकारी योगेश कुमार, निदेशक (वाणिज्य) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने मीडिया को दी। निदेशक का अयोध्या पहुंचने पर अधीक्षक अभियन्ता विनय कुमार ने बुके देकर स्वागत किया।

निदेशक ने बताया कि अयोध्या शहर में जेई टीजी-2 स्तर पर वर्टिकल सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे कार्यों का स्पष्ट विभाजन होगा और शिकायतों का निस्तारण तेजी से किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के तहत शहर में चार हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे, जो कौशलपुरी, राम की पैड़ी, अमानीगंज और लालबाग क्षेत्रों में संचालित होंगे।उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। शिकायतें ऑटो रैंडम सिस्टम के जरिए अलग-अलग कर्मचारियों को आवंटित होंगी, जिससे काम का दबाव बराबर बंटेगा और जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के कार्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियों में बांटा जाएगा।

निदेशक वाणिज्य ने यह भी बताया कि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसडीओ और जेई की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा सभी बिजली घरों पर सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य की जाएगी। इससे बिजली आपूर्ति और रखरखाव की निगरानी बेहतर हो सकेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर योगेश कुमार ने कहा कि आने वाले समय में कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था लागू की जाएगी और इसके लिए 33 केवी का अलग कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसी तरह तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर भी अलग-अलग व्यवस्थाएं होंगी।उन्होंने विश्वास जताया कि इन सुधारों से अयोध्या में बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सुचारु और उपभोक्ता-हितैषी बनेगी।

जबरन जमीन खाली कराने के प्रयास पर नजूल प्रशासन व पुलिस के खिलाफ तहरीर

» हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नगर के सिविल लाइन क्षेत्र में हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से डिक्रीदारों के पक्ष में फैसला और यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा जमीन खाली कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में नजूल प्रशासन और पुलिस के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है।डिक्रीदारों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं अरविन्द कौल, अतीक अहमद खान, लालजी गुप्ता, रोहित महरोत्रा एवं अंकित कनौजिया एडवोकेट ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिक्रीदारों को पहले ही परिसर पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि नजूल विभाग की आपत्ति के निस्तारण तक सभी पक्षकार मौके पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इसके बावजूद मंगलवार को स्थानीय जिला प्रशासन परिसर को खाली कराने पहुंच गया। प्रशासनिक अधिकारियों को जब हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की प्रतिलिपि दिखाई गई, तब भी जमीन खाली कराने का प्रयास किया गया, जो न्यायालय की खुली अवहेलना है। मौके पर डिक्रीदारों और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते प्रशासनिक अमला अपने मकसद में सफल नहीं हो सका और वापस लौट गया।पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए इस कथित गैरकानूनी प्रयास के दौरान परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को जबरन उखाड़कर ले जाया गया। इसी मामले को लेकर कोर्ट के आदेश से काबिज लोगों ने स्थानीय कोतवाली में नजूल प्रशासन और पुलिस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली और न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बना हाईटेक कंट्रोल रूम

» पुलिस विभाग की 12 हजार वर्ग फीट भूमि पर 1128.75 लाख की लागत से तैयार हुआ

दिसंबर 2023 में सीएंडडीएस ने शुरू कराया था निर्माण, जल्द होगा लोकार्पण

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ठीक बाहर पुलिस विभाग की 12 हजार वर्ग फीट भूमि पर एक आधुनिक प्रशासनिक भवन और कंट्रोल रूम का निर्माण पूरा हो चुका है। यह भवन 1128.75 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट को गृह विभाग द्वारा संचालित किया गया है। निर्माण कार्य दिसंबर 2023 में निर्माण संस्था सीएंडडीएस के माध्यम से शुरू हुआ था। जी प्लस वन मंजिला इस भवन में बेसमेंट में मुख्य कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। यह कंट्रोल रूम अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, जहां से सीसीटीवी फुटेज, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं का रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी।भवन में वेद मंदिर के निकट बने भवन में आंतरिक स्थल विकास कार्य के अंतर्गत कई आधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं। इनमें सीसी रोड (सीमेंट कंक्रीट रोड), रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाह्य जलमल निकासी व्यवस्था, वातानुकूलित (एयर-कंडीशन्ड) तंत्र, सबमर्सिबल पम्प के साथ बोरिंग, हाई-स्पीड लिफ्ट, पूर्ण विद्युतीकरण, मजबूत बाउंड्रीवाल, एमएस गेट और 160 केवीए का डीजल जनरेटर सेट प्रमुख है। ये सभी सुविधाएं भवन को पर्यावरण-अनुकूल, ऊर्जा-कुशल और आपात स्थिति में आत्मनिर्भर बनाती हैं।

हर गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर

कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के परियोजना प्रबंधक देवव्रत पवार ने बताया कि 98 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। बाउंड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है। यह भवन जल्द ही लोकार्पण के लिए तैयार है। लोकार्पण के बाद इसे पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। यह नया भवन विशेष रूप से पुलिस विभाग द्वारा संचालित होगा और राम जन्मभूमि परिसर के आसपास की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख सकेगा।

रीडगंज दुर्गेश्वरी माता मंदिर कमेटी का गठन

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

सर्वसम्मति से रोहित राणा सिंह बने कमेटी के अध्यक्ष

अयोध्या।रीडगंज स्थित श्री देवी दुर्गेश्वरी माता मंदिर में नववर्ष मिलन कार्यक्रम के अवसर पर 7 जनवरी को मंदिर कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से रोहित राणा सिंह को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।अध्यक्ष रोहित राणा सिंह ने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाएं सभी के सहयोग और आपसी तालमेल से ही सुचारू रूप से संचालित होंगी। उन्होंने मंदिर में होने वाले आयोजनों, पूजा-पाठ, भंडारे और दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बैठकें करने की बात कही। साथ ही अयोध्या के जिला व पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करते हुए पूर्व आयोजनों की सफल व्यवस्था के लिए आभार जताया। चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा करने पर चौकी इंचार्ज राणा दिग्विजय सिंह को भी कमेटी की ओर से धन्यवाद दिया।

हिंदुओं पर बर्बरता और भारत विरोध के बावजूद चुप्पी उठा रही सवाल

चावल के बाद भारत से डीज़ल खरीदेगा बांग्लादेश !

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

ढाका / नई दिल्ली । एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से एक लाख अस्सी हज़ार टन डीज़ल आयात करने का फैसला किया है। यह निर्णय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में लिया गया है। इस आयात के लिए बांग्लादेश ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ चौदह अरब बासठ करोड़ टका का समझौता किया है।

इस समझौते के तहत डीज़ल की खरीद बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के माध्यम से की जाएगी। भुगतान का एक हिस्सा सरकारी स्तर पर किया जाएगा, जबकि शेष राशि बैंकों से ऋण लेकर चुकाई जाएगी। डीज़ल की आपूर्ति असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से भारत-बांग्लादेश मैत्री नलिका मार्ग के ज़रिये की जाएगी।

विदेश नीति पर उठे सवाल !

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह सवाल तेज़ हो गया है कि क्या केवल व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के नाम पर भारत-विरोधी मानसिकता और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की अनदेखी उचित है?
क्या आर्थिक सहयोग से पहले पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के प्रति सम्मान की गारंटी नहीं होनी चाहिए?
गौरतलब है कि बांग्लादेश ने इससे पहले भारत से चावल आयात का भी फैसला किया था। ऐसे में लगातार हो रहे व्यापारिक समझौतों को लेकर यह बहस तेज़ है कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत हितों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

बांग्लादेश को डीज़ल आपूर्ति का यह फैसला आर्थिक दृष्टि से भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन भारत-विरोधी कट्टरता और हिंदुओं पर अत्याचार के बीच ऐसे समझौते करना कई सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते निभाते समय राष्ट्रीय स्वाभिमान और हिंदू समाज की अस्मिता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

कारोबारी रिश्ते, लेकिन जमीनी हकीकत अनदेखी

इस डीज़ल समझौते को जहां दोनों देशों के बीच ऊर्जा और व्यापार सहयोग के रूप में देखा जा रहा है, वहीं बांग्लादेश में भारत-विरोधी कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियां और वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही बर्बरता को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी समूह खुले तौर पर भारत के खिलाफ ज़हर उगलते रहे हैं। इसके साथ ही हिंदू समुदाय के मंदिरों, घरों और धार्मिक प्रतीकों पर हमले, जबरन पलायन और सामाजिक उत्पीड़न की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। इसके बावजूद भारत द्वारा ऐसे हालात को नज़रअंदाज़ कर बड़े कारोबारी रिश्ते निभाना हिंदू अस्मिता और सुरक्षा के साथ समझौता माना जा रहा है।

बनारस में 'उल्टी' वोटर लिस्ट, ढहे मकानों के पते पर भी दर्ज मतदाता

- एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में काशी विश्वनाथ धाम में समाए भवनों के नाम शामिल
- जहां मकान बचे, वहां वोट कट गए, शिकायत पर प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

वाराणसी। बनारस में ÷उल्टी गंगा बहती है÷ सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में भी यह सच्चाई सामने आ गई है। एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में ऐसा दृश्य देखने को मिला है, जो सामान्य तर्कों को उलट देता है। जहां प्रदेश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने से सियासी हलचल मची है, वहीं बनारस में उन मकानों के पते पर भी मतदाताओं के नाम दर्ज मिले हैं, जिनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है।

मंगलवार को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद बुधवार को स्थानीय नागरिकों ने जब ऑनलाइन मतदाता सूची की पड़ताल की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के तहत ध्वस्त किए गए भवनों के पते अब भी मतदाता सूची में मौजूद पाए गए। कालिका गली स्थित भवन संख्या डी-8/34 में रंजू झा और साक्षी झा के नाम मतदाता के रूप में दर्ज हैं, जबकि यह भवन अब धाम परियोजना में विलय हो चुका है। इसी तरह लाहौरी टोला के भवन संख्या डी-1/59 में दीपक मिश्र, सूरज मिश्र और राजकुमार के नाम सूची में मौजूद हैं, जबकि ये लोग अब वहां निवास नहीं करते।

हैरानी की बात यह भी है कि जिन भवनों का अस्तित्व अब भी बना हुआ है और जहां दर्जन भर से अधिक मतदाता रह रहे हैं, वहां के कई लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से गायब मिले। प्रभावित मतदाताओं का कहना है कि

उन्होंने एसआईआर के दौरान मांगी गई सभी जानकारियां और दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए थे, इसके बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए।

इस विसंगति पर एडीएम (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम गलत पते पर दर्ज हैं या स्थानांतरण की आवश्यकता है, उन्हें फॉर्म-8 भरवाकर उनके वास्तविक निवास स्थान के बूथ पर स्थानांतरित किया जाएगा।

बनारस में सामने आई यह स्थिति न केवल एसआईआर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर रही है।

स्मार्ट मीटर सिस्टम फेल, एक लाख उपभोक्ताओं का बैलेंस शून्य

- 11 दिसंबर को एसएटी बाधित, पश्चिमांचल के 13 जिलों में बिगड़ी शुल्क गणना
- एमडीएम सिस्टम में खामियां उजागर, उपभोक्ता परिषद ने जांच की मांग उठाई

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (पीवीवीएनएल) में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था की बड़ी खामी सामने आई है। सिस्टम में बार-बार आई तकनीकी खराबी के कारण पश्चिमांचल के 13 जिलों में करीब एक लाख उपभोक्ताओं का बिजली बैलेंस अचानक शून्य हो गया। इससे बिजली खपत और बैलेंस की गणना पूरी तरह प्रभावित हो गई।

यह गंभीर मामला हाल ही में पावर कॉरपोरेशन की समीक्षा बैठक में उजागर हुआ, जहां पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने स्वीकार किया कि पूरा सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो गया था। निगम के अनुसार 11 दिसंबर को साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट (एसऐटी) कई बार बाधित हुआ, जिसके चलते एक लाख से अधिक स्मार्ट मीटरों में शुल्क गणना प्रणाली फेल हो गई।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बागपत, शामली, हापुड़, अमरोहा और संभल जिले आते हैं। निगम ने यह भी बताया कि वह अपने पूरे डाटा के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर (ऐएमआईएसपी) पर पूरी तरह निर्भर है, लेकिन दस महीने बीत जाने के बाद भी डाटा निकालने का कोई वैकल्पिक सिस्टम विकसित नहीं हो सका है।

समीक्षा बैठक में यह भी सामने आया कि नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब तक मीटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम (एमडीएमएस) में शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे फीडर स्तर की ऊर्जा लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रभावित हो रही है। शामली जैसे जिलों में कई उपभोक्ताओं ने रिचार्ज कराने के बावजूद कई दिनों तक बिजली आपूर्ति नहीं मिलने की शिकायत की। इसका कारण आउटडेटेड उपभोक्ता ऐप और गलत डाटा बताया गया।

स्मार्ट मीटरः एक नजर में

10 82, 666 स्मार्ट प्रीपेड मीटर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में लगे

56 लाख से अधिक पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके

37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में बदल गए

34 लाख मीटरों का साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा हो चुका है

इस पूरे मामले पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गंभीर चिंता जताई है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के एमडीएम सिस्टम में कई खामियां पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अब तक छुपाया जाता रहा। उन्होंने स्मार्ट मीटर व्यवस्था की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है।